फ़रीदाबाद स्मार्ट सिटी का ख्वाब और जमीनी हकीकत

बडखल गांव से दिनेश की रिपोर्ट

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 28 अप्रैल 2018 को फ़रीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिये 1847 करोड़ रुपये खर्च करने का एलान किया। शहर को स्मार्ट बनाने के लिये, फ़रीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी का गठन किया गया। इस कंपनी की मीटिंग में स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर और उद्योग मंत्री विपुल गोयल भी शामिल थे।

मीटिंग में स्पेन की कंपनी ने शहर में बनाये जाने वाले कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का प्लान दिखाया। फ़रीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिये फ्रांस की कंपनियों ने भी सहायता राशि देने की पेशकश की। इस मिशन में 2600 करोड़ रुपये का कुल खर्चा आयेगा जिसमें से 500 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार देगी, 500 करोड़ रुपये हरियाणा सरकार देगी और बाकि 1600 करोड़ रुपये फ़रीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड जुटायेगी। यह 1600 करोड़ कर्जा लेकर और जनता से टैक्स लगाकर वसूला जायेगा।

स्मार्ट सिटी की सुविधायें–न्यूयार्क, लंदन और पेरिस जैसी होगी इसमें पानी की भरपूर आपूर्ति होगी। साफ़ सुथरा वातावरण होगा। गरीबों के लिये सस्ते मकान होंगे। शहर में इंटरनेट सुविधा से युक्त और डीजिटलाइज्ड होगा। सभी नागरिकों की भागीदारी होगी। फ़रीदाबाद भी अब लंदन, पेरिस और न्यूयार्क बन जायेगा। पर हकीकत क्या है ?

जमीनी हकिकत ! फ़रीदाबाद में 137 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्र है और 214 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है। फ़रीदाबाद में 66 गांव है, 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी 1594839 थी। फ़रीदाबाद के 66 गांवों की हालत न तीतर है न बटेर है इनमें से कुछ गांव तो फ़रीदाबाद नगर निगम के अंदर भी आते हैं। नगर निगम के शहरी इलाकों में चौड़ी सड़कें है। सीवरेज की सुविधा है। साफ़ सफ़ाई है। लोग़ों का ऊंचा जीवन स्तर है। यही वायदा नगर निगम के अंदर आने वाले गांवों के लिये भी किया गया।

नगर निगम के अंदर बड़खल गांव भी आता है जिसमें अनेकानेक समस्यायें है जो दिन–रात गांव वालों को परेशान करती रहती है। गांव में गंदगी का ढेर लगा रहता है। बच्चों के खेलने का पार्क नहीं है, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र नहीं है, पीने के साफ़ पानी की किल्लत है। शमशान घाट और कब्रिस्तान की बद्तर हालत है। सरकारी स्कूल की जर्जर हालत है। मुख्य रास्ता उबड–खाबड़ और कीचड़ से भरा रहता है जिसमें पैदल आने जाने वाले गिरते रहते हैं। गांजा–अफ़ीम के नशे का अवैध कारोबार है, सट्टेबाजी का अवैध धंधा है, गांव की सार्वजनिक जमीन और जोहड़ पर अवैध कब्जा और प्लॉटिंग करके कॉलोनी बसाने का धंधा है, यह सब कार्य शासन–प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे उनकी मिली भगत से होता है।

यह सब देख कर लगता है कि क्या यह भी उसी फ़रीदाबाद का हिस्सा है जो स्मार्ट बनाया जायेगा ? इन समस्याओं से ग्रस्त होकर नौजवानों ने सरकार, नगर निगम, पार्षद, विधायक और केन्द्रीय मंत्री सभी को प्रार्थनापत्र दिये कि जल्द से जल्द इन का समाधान किया जाये। उन से हर बार झूठा आश्वासन और अगली तारीख मिली। जब कोई ज़मीनी कार्य नहीं हुआ तो नौजवानों ने गांव वालों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण धरना–प्रर्दशन भी किया। इसके बावजूद गूंगी–बहरी विधायक सीमा त्रिखा और नगर निगम के कानों पर जूं तक न रेंगी।

फ़रीदाबाद के बहुसंख्यक गांवों की यही बद्तर हालात है। क्या इतनी बड़ी आबादी को छोड़ कर स्मार्ट सिटी बनाने का सपना पूरा होगा ? फ़रीदाबाद बासियों को ये समझ लेना चाहिये कि यह शहर लंदन, पेरिस, न्यूयार्क जैसा बनने वाला तो क्या, यहां कोई मूलभूत सुधार भी होने वाला नहीं है।

जब तक यहां की सत्ता चोरों, डाकुओं के हाथ में रहेगी, 2600 करोड़ तो क्या 26 लाख करोड़ भी इन्हें दे दिये जायें तो भी ये कुछ करने वाले नहीं है। अभी तो स्मार्ट सिटी के नाम पर दो–चार अफ़सरों के छोटे–मोटे विदेशी दौरे लगे हैं, बड़ी रकम मिलने पर और अधिक अफ़सरों व नेताओं के लम्बे–लम्बे विदेशी दौरे लगेंगे। विदेशी कम्पनियों को बड़े–बड़े ठेके देकर मोटे–मोटे कमिशन डकारने के रास्ते तैयार किये जायेंगे।

मामला सिर्फ किसान या "अन्नदाता" का नहीं है, मामला पूरे खेती के ढांचे का है

मजदूर मोर्चा विशेष

दिल्ली में पूरे देश से आए किसान एक बढ़ी चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.उन्होंने किसान मैनीफेस्टो भी जारी किया है.यह आन्दोलन ऐसे समय में हो रहा है जब सरकार कारपेरेट फार्मिंग के पक्ष में नीति सम्बन्धी अनेक फैसले लेने का मन पूरी तरह बना चुकी है और इस दिशा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनेक कदम उठा रही है.भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी बिल वह पास नहीं कर सकी है लेकिन उसे लागू करने की परिस्थिति काफी हद तक तैयार कर ली गई है.

आदिवासियों के जमीन और जंगल सम्बन्धी अधिकारों पर हमला हो या खेती को लगातार अपूरणीय घाटे में धकेलने की कोशिशें सब एक ही दिशा बना रहे हैं.डिमानेटाई ?शन का एक लक्ष्य छोटे किसान और व्यापारी के धंधे को ऐसे नुकसान में धकेलना था जहां से वह निकल न सके और कार्पोरेट पूंजी का रास्ता नीचे तक बन सके.

किसान खेती पर 21दिन का विशेष अधिवेशन संसद से मांग रहे हैं ताकि खेती से जुड़ी बुनियादी समस्याओं पर बात हो सके.क्या यह मांग ज्यादा है ? खेती सब लोगों से जुड़ा सवाल है.खाद्य –सुरक्षा से लेकर रोजगार और शहरों के संतुलित विकास तक के असंख्य मामले खेती की हालत और उसके ढांचे से जुडे हैं. जनस्वास्थ्य और आम साधारण लोगों की खरीदने की ताकत भी खेती से जुड़ी है.

इस ताकत का सम्बन्ध बाजार के विस्तार से भी है और शिक्षा के विस्तार से भी है.अन्न का कम उत्पादन, साधारण व्यापक आबादियों की पहुंच का उससे दूर होते जाना,उसका अभाव ये निकट भविष्य में प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष अकाल के सिलसिले को न्यौता देना है.मौजूदा विश्व कार्पोरेट पूंजीऔर उसका हिमायती शासक वर्ग लोगों को भूख, कुपोषण और उससे जुड़ी बीमारियों से "स्वाभाविक" मौत की ओर धकेल रहे हैं.इसके पीछे आबादियों का बड़े पैमाने पर सफाया और संसाधनों की सुनियोजित पद्धति है.लोगों को इतना शक्तिहीन कर दो कि वे प्रतिरोध न कर सकें, जीवित रहने के लिये गुलामी करने लगें,"फालतू" आबादियां "अपने आप" खुद–ब–खुद उतम हो जायें,गुलाम बन जाएं .वर्ना क्या कारण है कि खेती प्राथमिकता में नहीं है उल्टे उसे उजाड़ने की नीति तैयार की गई हैं.यह किसानों का मसला नहीं है .

जा!हिर है तीन लाख किसानों की आत्महत्या को सवा अरब की आबादी में "स्मार्ट" लोग और "स्मार्ट" शासक वर्ग बहुत मामूली मानता है जबकि उसे लाखों में करोड़ों की संख्या में आबादी का सफाया करना है,उन्हें "नियन्त्रित" करना है.

किसानों और उनके नेताओं को यह गलतफहमी नहीं है कि सरकार किसान मैनीफेस्टो पर ध्यान देगी फिर भी वे दिल्ली आए हैं, सिर्फ मांग करने नहीं वे अपना दावा रखने भी आए हैं,वे सिर्फ कर्जा–मुक्ति और लाभकारी मूल्यों के लिये नहीं जमीन के अधिकार के लिये भी आए.खेती करने वाले भूमिहीनों के लिये पट्टे का प्रस्ताव भी लाये हैं जिसमें महिला किसान, उजड़े हुए किसान, आदिवासीयों के जल, जंगल, जमीन के अधिकार, खेतमजदूर, बटाईदार भूमिहीन भी शामिल हैं .

मामाला सिर्फ किसान या "अन्नदाता"का नहीं है मामला पूरे खेती के ढांचे का है.मौजूदा किसान आन्दोलन और किसान मार्च लम्बे स्थानीय और राज्यस्तरीय आन्दोलनों की एक निरन्तर, व्यापक शृंखला से बना है.इसकी खास बात ये है कि बुद्धिजीवी, छात्र, शहरी आबादी का एक हिस्सा, पत्रकार, फोटो पत्रकार ट्रेड यूनियन, बैंक कर्मचारी, आई टी मजदूर यूनियन ,कलाकार, लेखक टीचर्स एसोसिएशन आदि अनेक तबके इस आन्दोलन के समर्थन में आ रहे हैं.खेती सम्बन्धी वैकल्पिक पालिसी पर सुसंगत काम इसके पीछे है. यह किसानों के स्वतन्त्र आन्दोलनों की व्यापक एकता से बना मार्च है.इसकी संरचना महत्वपूर्ण है.यह एक ऐतिहासिक मार्च है जिसमें प्रतिपक्ष को चुनौती देने की गहरी संभावना है . यह आन्दोलन किसान और व्यापक समाज के बीच एक पुल भी बना रहा है.यह फासीवाद के रास्ते में एक अड़चन भी है.

इस आन्दोलन के अन्दर और बाहर की अनेक चुनौतियों के बावजूद इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है भविष्य में यह एक निर्णायक भूमिका अदा करे.सवाल यह भी है कि व्यापक समाज और प्रतिरोध के अन्य आन्दोलनों व किसान आन्दोलन के बीच के अन्तर्सूत्र कितने खुल पायेंगे.

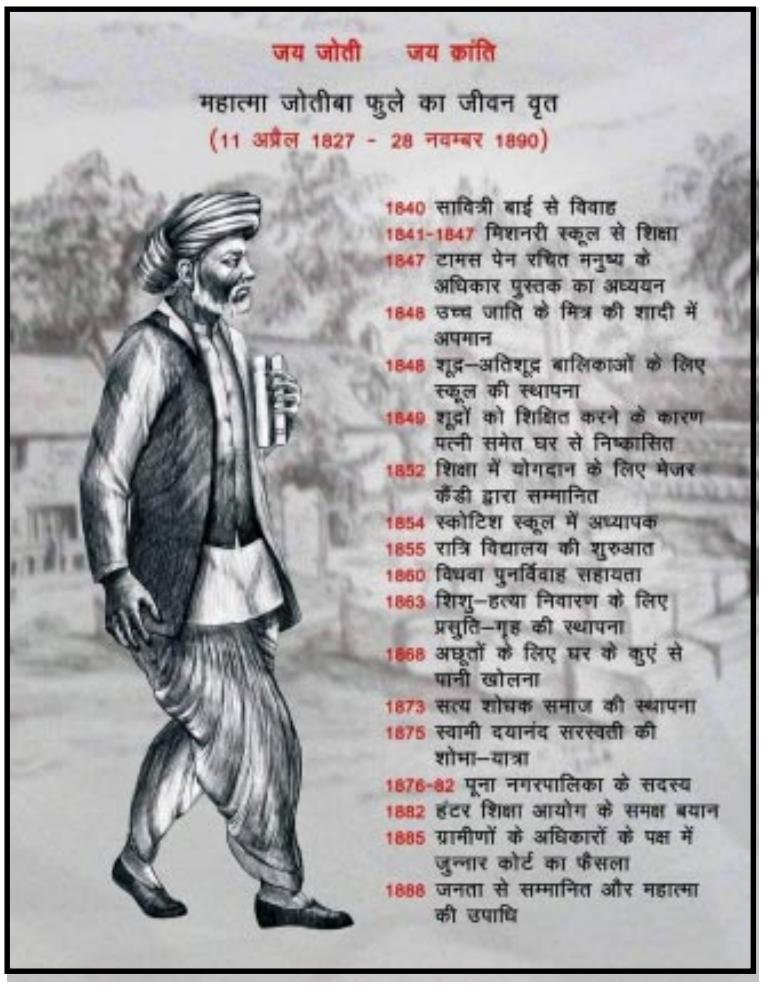

ईएसआई अस्पताल सेक्टर 8 में 18 साल से अल्ट्रा साऊंड मशीन नहीं, मरीज़ भटकने को मजबूर

फ़रीदाबाद (म.मो.) सेक्टर 8 का ईएसआई अस्पताल हरियाणा की खट्टर सरकार के जिम्मे है। केवल चलाने का ही जिम्मा है खर्चे का नहीं। खर्चे का 88 प्रतिशत ईएसआई कार्पोरेशन अदा करती है। इसके बावजूद जुमलेबाज पार्टी की सरकार ने इस अच्छे भले अस्पताल की मिट्टी पलीत कर रखी है। सन् 1994 में यहां के लिये एक अल्ट्रा साऊंड मशीन खरीदी गयी थी जिसका कार्यकाल 6 साल चलने के बाद सन् 2000 में पूरा हो गया। उसके बाद आज तक वह मशीन खरीदी नहीं गयी है। मजे की बात तो यह है कि 30–40 लाख की इस मशीन के लिये हर बजट में प्रावधान तो किया जाता है, परन्तु मशीन खरीदी नहीं जाती। पांच–छ:करोड़ का बजट हर साल लैप्स कराना मंजूर है परन्तु मशीन नहीं खरीदनी।

विदित है कि इस अस्पताल की बिल्डंग 200 बेड के लिये बनाई गयी थी लेकिन इसमें चलाया जा रहा है मात्र 50 बेड का अस्पताल, डॉक्टरों स्टाफ़ व उपकरण आदि के न होने की वजह से 50 में से भी मात्र 10–12 बेड पर ही मरीज़ रहते है। चिकित्सा के नाम पर 'आयुष्मान भारत' की ड्रामेबाजी करने वाली जुमलेबाजों की यह सरकार इसी अस्पताल में 17 डॉक्टरों की बजाय यदि 100–150 डॉक्टर तथा स्टाफ़ व उपकरण आदि उपलब्ध करा दे तो इस क्षेत्र के उन लाखों गरीब मजदूर परिवारों को चिकित्सा लाभ मिल सकता है जिनके वेतन से सरकार का ईएसआई कार्पोरेशन हर माह वेतन का साढे 6 प्रतिशत झटक लेता है।

अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा न होने के चलते यह अस्पताल इलाज करने के बजाय रैफ़र करने मात्र के लिये रह गया है। विदित है कि रैफ़र होने वाले मरीज़ों को पहले एनएच–3 के धक्के खाने पड़ते हैं, उसके बाद आवश्यक हो तो अन्य अस्पतालों के। अब एक अल्ट्रासाऊंड मशीन के अभाव में मरीजों को 5–6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और वहां भी काम तो 7 मशीनों का है और मशीने हैं केवल दो। जाहिर है ऐसे में मरीज को 2 से 3 माह की तारीख ही मिलेगी। चिकित्सा के नाम पर यह तमाशा नहीं तो और क्या है ? इस तरह का तमाशा करने वाले शासकों को जुमलेबाज नहीं तो और क्या कहा जा सकता है।